REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.2331 (UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 7 | APRIL - 2018

पंजाब नेशनल बैंक की कार्यशील पूँजी के आधार पर लाभक्षमता का विश्लेषण आर्थिक उदारीकरण के सन्दर्भ में

डॉ. मनीष कुमार जैन
सहायक प्राध्यापक , रुकमादेवी पन्नालाल लड्ढा माहेश्वरी महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

➢ प्रस्तावना

बैंको की प्रतियोगी कार्यकुशलता तथा परिचालनगत लचीलेपन में वृद्धि की दृष्टि से बाजार प्रवृत्तियों पर अधिक ध्यान देते हुए वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों का प्रथम चरण आरंभ हुआ, ताकि बैंक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना कर सकें और वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण इत्यादी के कारण उत्पन्न होने वाली विनिमयकारी और पर्यवेक्षी माँग को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नरसिंहम समिति का गठन किया गया। नरसिंहम समिति का पहला चरण (आर्थिक उदारीकरण का प्रथम दौर) एक तरह से सुधारात्मक था जबकि दूसरे चरण (आर्थिक उदारीकरण का द्वितीय दौर) में प्रथम चरण के लाभों को समेकित करने पर बल दिया जा रहा है।

देश के आर्थिक विकास में बैंकिंग उद्योग के महत्व को देखकर यह कहा जा सकता है कि बैंकिंग उद्योग को लाभ में बने रहकर ही अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। इसी संदर्भ में जनवरी 1991 में, बैंगलूर में, बैंक अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन में की गई यह टिप्पणी आज भी अपना महत्व दर्शाती है:—

''वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था पर अपना भार यदि नहीं डालना है तो हमें यह समझना होगा कि सरकारी क्षेत्र के लिए लाभ उतना ही महत्वपूर्ण है जितना निजी क्षेत्र के लिए। हमें यह भी समझना होगा कि अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने हेतु तथा पर्याप्त अतिरेक उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र को अपना लाभ बढ़ाना ही होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को अपनी लागत न्यूनतम रखने के साथ—साथ अपनी आय तथा लाभप्रदता को अनुकूलतम करना होगा ताकि वे अपने स्थायित्व तथा नवीनतम प्रगति को सतत रख सकें। यदि समग्र उद्देश्यों की पूर्ति के बाद लाभ का प्रवाह होता है तो यह निश्चित ही गर्व का विषय है।

यहाँ पर यह समझना आवश्यक होगा कि यदि किसी देश का बैंकिंग उद्योग ही लाभ एवं लाभक्षमता के प्रति सचेत नहीं होगा तो उस देश के अन्य उद्योगों के अस्तित्व के बारे में तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। अतः बैंको को अपनी लाभक्षमता में वृद्धि दर्ज करते रहना आवश्यक हो गया है।''

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बैंको के समक्ष लाभक्षमता में वृद्धि करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में भारतीय बैंक, विदेशी बैंको से सक्षमतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकें एवं प्रोद्योगिकी विकास के अनुरूप भारतीय बैंकिंग में परिवर्तन किया जा सके।

➢ शोध के उद्देश्यः—

बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित उपर्युक्त परिदृश्य का अवलोकन करने के पश्चात् प्रस्तुत शोध **पत्र** के निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये :—

1. नवीन आर्थिक परिवेश में कार्यशील पूँजी के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक की लाभक्षमता प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।
2. लाभक्षमता से संबंधित **तथ्यों** का अध्ययन करना।

➢ पूर्व शोध कार्यों का सर्वेक्षण

बैंको की लाभदेयता अर्थशास्त्रियों और विचारकों के लिए कोई नया विषय नहीं है, अपितु इस दिशा में विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने अपने स्तर पर शोधकार्य किए गए हैं। प्रस्तुत शोध हेतु कार्य करने के पूर्व इनमें से अनेक शोध कार्यों का संक्षिप्त सर्वेक्षण किया गया है –

अभय सी पारीख तथा एस. आर. कृष्णमूर्ति ने 'Profitability An-Index of Performance of Fourteen Nationalised Banks' के अन्तर्गत सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रयोग करके लाभदायकता का अध्ययन किया। उन्होंने पाँच वर्ष की समयावधि (1969–73) लेकर लाभदायकता को लाभ व कार्यशील निधि व आय से अनुपात तथा रिजर्व व जमाओं से अनुपात के रूप में व्यक्त किया। उनके अनुसार 1969 में लाभ का कार्यशील निधि से अनुपात सर्वाधिक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का तथा सबसे कम इण्डियन बैंक का था, जबकि यही अनुपात 1970–73 में सर्वाधिक यूनाईटेड कमर्शियल बैंक का रहा।

डी. डी. डीवान्टा और टी. आर. वेंकटचलम "Operational Efficenency and Profitability of Public Sector Banks" के अन्तर्गत लाभदायकता का चयनित 15 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यकुशलता को मापने के लिए तीन संकेतकोंः परिचालन कार्यकुशलता उत्पादकता के रूप में, परिचालन कार्यकुशलता स्थानिक एवं क्षेत्रीय उद्देश्य के रूप में प्रयोग किया। उन्होंने उपर्युक्त तीनों संकेतकों द्वारा बैंको की कार्यकुशलता का श्रेणी विधि द्वारा अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि चयनित बैंको की लाभदायकता में अध्ययन अवधि के दौरान कमी हुई है।

एस. सी. सरकार ने "Profitability of Commercial Banks" के अन्तर्गत सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रयोग करके बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की लाभदायकता में राष्ट्रीयकरण के बाद कमी हुई है, जबकि बैंको की शाखाओं व जमाओं में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने लाभदायकता को लाभ के आय व जमाओं से प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया।

एम. पी. एन. नंबूद्रीपाद (1988) ने ''बैंक शाखा में लाभप्रदता कुछ समस्याएँ'' विषय पर एक अध्ययन किया। उन्होंने बैंकों में घाटे के कारणों को बताते हुए लाभप्रदता में सुधार लाने की प्रवृत्ति से सम्बन्धित सुझाव दिए।

डी. भट्टाचार्य और एस. आर. सुब्बाराव (1988) ने ''शाखा बैंकिंग और लाभदायकता'' विषय पर एक अध्ययन किया। उन्होंने शाखाओं द्वारा लाभों को बढ़ाने की आवश्यकता बताते हुए, इसमें क्षेत्रीय प्रबन्धकों का योगदान तथा मानव शक्ति विकास व प्रशिक्षण का महत्व बताया।

➢ शोध प्राक्कल्पना :–

कार्यशील पूँजी के आधार पर बैंक की लाभक्षमता में आर्थिक उदारीकरण के प्रथम दौर की तुलना में द्वितीय दौर में वृद्धि हुई है।

➢ शोध प्रविधि :–

शोध प्रबंध के लिए निम्नलिखित प्रविधि का अनुसरण किया गया हैः–

1. नवीन आर्थिक परिवेश में बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करने वाले निर्देशों का अध्ययन विभिन्न शासकीय परिपत्रों, राजपत्र प्रकाशनों के आधार पर किया गया है।
2. लाभक्षमता के मापन के लिए कार्यशील पूंजी पर लाभ का प्रतिशत प्रवृत्ति का प्रतिशत के आधार पर विश्लेषण किया गया है।
3. नवीन आर्थिक परिवेश के अन्तर्गत बैंक की लाभानुपात प्रवृत्तियों का अध्ययन भी किया गया है।

➢ समंक संकलन एवं विश्लेषण :

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध पूर्ण रूप से द्वितीयक समंको पर आधारित है। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की गत् वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट, आई बी. ए. बुलेटिन तथा भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न प्रकाशनों के आधार पर आवश्यक समंको का एकत्रीकरण और सारणीयन किया गया है। समंको का सारणीयन आर्थिक उदारीकरण का प्रथम दौर (वर्ष 1991–92 से वर्ष 1997–98 तक) तथा आर्थिक उदारीकरण का द्वितीय दौर (वर्ष 1998–99 से वर्ष 2004–05 तक), दो भागों में विभाजित कर किया गया है। सारणीयन के पश्चात् इन समंको को विभिन्न सांख्यिकीय विधियों जैसे :– औसत, प्रमाप विचलन एवं विचरण गुणांक आदि की सहायता से विश्लेषित कर निष्कर्ष निकालने के प्रयास किये गये हैं।

तालिका क्रमांक (अ)
पंजाब नेशनल बैंक की लाभक्षमता की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)
(कार्यशील पूँजी के आधार पर)
आर्थिक उदारीकरण के प्रथम दौर में
वर्ष 1991–92 से 1997–98 तक

(राशि करोड़ रूपये में)

वर्ष	शुद्ध लाभ	कार्यशील पूंजी	लाभक्षमता (कार्यशील पूंजी पर लाभ का प्रतिशत)	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
1991–92	112.44	436.78	25.74	–
1992–93	38.01	548.78	6.93	– 73.08
1993–94	74.52	789.07	9.44	+ 36.22
1994–95	85.79	1265.56	6.78	– 28.18
1995–96	– 9,59,218 रू.	1161.07	–	–
1996–97	237.70	1342.07	17.71	+ 161.21
1997–98	477.35	1654.14	28.86	+ 62.96

स्त्रोत : बैंक की विभिन्न वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट्स

समयावधि के प्रथम व अन्तिम वर्ष की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि आर्थिक उदारीकरण के प्रथम दौर में बैंक के शुद्ध लाभों में लगभग 4.25 गुना की वृद्धि हुई है।

पंजाब नेशनल बैंक की कार्यशील पूंजी के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1991–92 में बैंक की कार्यशील पूंजी 436.78 करोड़ रू. थी जबकि वर्ष 1997–98 में बढ़कर 1654.14 करोड़ रू. हो गई। प्रथम दौर के इन 7 वर्षों में कार्यशील पूंजी में लगभग 1217.36 करोड़ रू. की वृद्धि हुई, यदि वार्षिक वृद्धि की बात करें तो बैंक की कार्यशील पूंजी में लगभग 173.91 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष औसत वृद्धि हुई है। आर्थिक उदारीकरण के इस प्रथम दौर में बैंक की कार्यशील पूंजी में लगभग 3.79 गुना की वृद्धि हुई है। पंजाब नेशनल बैंक की लाभक्षमता अर्थात् कार्यशील पूंजी पर लाभ का प्रतिशत देखें तो ज्ञात होता है कि वर्ष 1991–92 में बैंक का उक्त प्रतिशत 25.74 प्रतिशत था जबकि बाद के वर्षों में इसमें बहुत अधिक गिरावट पायी गई साथ ही वर्ष 1995–96 में यह शून्य के स्तर तक आ गई परंतु वर्ष 1996–97 व 1997–98 में क्रमशः 17.71 प्रतिशत तथा 28.86 प्रतिशत की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। गत् वर्ष की तुलना में प्रतिशत का अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि इस समयावधि में 2 बार ऋणात्मक परिवर्तन तथा 3 बार धनात्मक परिवर्तन हुआ है।

उक्त तालिका के सांख्यिकीय विश्लेषण से ज्ञात होता है कि आर्थिक उदारीकरण के प्रथम दौर में पंजाब नेशनल बैंक की लाभक्षमता अर्थात कार्यशील पूंजी पर लाभ का औसत प्रतिशत 13.64 प्रतिशत था, इसका प्रमाप विचलन 9.93 तथा विचरण गुणांक 72.80 प्रतिशत रहा है। परिवर्तन की गति का औसत प्रतिशत 26.52 प्रतिशत रहा जबकि प्रमाप विचलन 74.36 तथा विचरण गुणांक 280.39 प्रतिशत रहा।

तालिका क्रमांक (ब)
पंजाब नेशनल बैंक की लाभक्षमता की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)
(कार्यशील पूँजी के आधार पर)
आर्थिक उदारीकरण के द्वितीय दौर में
वर्ष 1998–99 से 2004–05 तक

(राशि करोड़ रूपये में)

वर्ष	शुद्ध लाभ	कार्यशील पूंजी	लाभक्षमता (कार्यशील पूंजी पर लाभ का प्रतिशत)	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
1998–1999	372.11	1929.75	19.28	–
1999–2000	408.13	2272.58	17.96	– 6.85
2000–2001	463.64	2669.20	17.37	– 3.29
2001–2002	562.39	3380.68	16.64	– 4.20
2002–2003	842.20	4033.00	20.88	+ 25.48
2003–2004	1108.68	5011.83	22.12	+ 5.94
2004–2005	1410.12	8161.29	17.28	– 21.88

स्त्रोत : बैंक की विभिन्न वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट्स

आर्थिक उदारीकरण के द्वितीय दौर में पंजाब नेशनल बैंक की लाभक्षमता की प्रवृत्ति हेतु दर्शायी गई तालिका क्र.(ब) का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 1998–99 में बैंक के शुद्ध लाभ 372.11 करोड़ रूपये थे, यह शुद्ध लाभ की राशि वर्ष 2004–05 में 1410.12 करोड़ रूपये हो गई। इस प्रकार शुद्ध लाभ की राशि में लगभग 1038.01 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई। शुद्ध लाभ की राशि में हुई यह वृद्धि लगभग 148.29 करोड़ रूपये औसतन प्रतिवर्ष वृद्धि है। आर्थिक उदारीकरण के द्वितीय दौर में शुद्ध लाभ में लगभग 3.79 गुना की वृद्धि दर्ज की गयी है।

द्वितीय दौर के कार्यशील पूँजी के आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 1998–99 में बैंक की कार्यशील पूँजी 1929.75 करोड़ रूपये थी जो बढ़कर वर्ष 2004–05 में 8161.29 करोड़ रूपये हो गई, इस समयावधि में कार्यशील पूँजी की मात्रा में कुल 6231.54 करोड़ रूपये की वृद्धि पायी गई। इस प्रकार कार्यशील पूँजी की मात्रा में लगभग 890.22 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष औसत वृद्धि हुई है। आर्थिक उदारीकरण के द्वितीय दौर में कार्यशील पूँजी में लगभग 4.23 गुना की वृद्धि हुई है।

कार्यशील पूँजी पर लाभ का प्रतिशत दर्शाता है कि वर्ष 2001–02 में बैंक की लाभक्षमता सबसे न्यूनतम स्तर 16.64 प्रतिशत पर थी जबकि वर्ष 2003–04 में बैंक की लाभक्षमता 22.12 प्रतिशत के साथ सबसे अधिकतम स्तर पर रही। यहाँ यह कहना उचित होगा कि आर्थिक उदारीकरण के द्वितीय दौर में बैंक की लाभक्षमता में बहुत अधिक उतार–चढ़ाव नहीं रहा, अतः कह सकते हैं कि इस समयावधि में बैंक लाभक्षमता को नियंत्रित करने की स्थिति में रही। गत् वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि वर्ष 2004–05 सबसे अधिक ऋणात्मक परिवर्तन 21.88 प्रतिशत रहा जबकि सर्वाधिक धनात्मक परिवर्तन वर्ष 2002–03 में 25.48 प्रतिशत पाया गया। इस समयावधि में चार बार ऋणात्मक परिवर्तन रहा जबकि दो बार धनात्मक परिवर्तन की स्थिति रही। आर्थिक उदारीकरण के द्वितीय दौर में पंजाब नेशनल बैंक की लाभक्षमता अर्थात कार्यशील पूँजी पर लाभ का औसत प्रतिशत 18.79 प्रतिशत था, इसका प्रमाप विचलन 1.90 तथा

विचरण गुणांक 10.13 प्रतिशत रहा है। परिवर्तन की गति का औसत प्रतिशत 0.8 प्रतिशत रहा जबकि प्रमाप विचलन 14.35 तथा विचरण का गुणांक 1793.22 प्रतिशत रहा।

उपर्युक्त तालिकाओं के तुलनात्मक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि **पंजाब नेशनल बैंक की लाभक्षमता कार्यशील पूँजी के आधार पर आर्थिक उदारीकरण के द्वितीय दौर में अधिक स्थिर रही है**, जबकि परिवर्तन की गति के अनुसार आर्थिक उदारीकरण के प्रथम दौर में लाभक्षमता में धनात्मक परिवर्तन की प्रवृत्ति अधिक पायी गयी।

➢ परिकल्पना सत्यापन :–

कार्यशील पूँजी के आधार पर बैंक की लाभक्षमता में आर्थिक उदारीकरण के प्रथम दौर की तुलना में द्वितीय दौर में वृद्धि हुई है। अतः उक्त परिकल्पना सत्य सिद्व होती है।

➢ शोध की सीमाएं :–

प्रस्तुत शोध **पत्र** को निम्नलिखित सीमाओं में समेटने का प्रयास किया गया है:–

1. शोध में केवल द्वितीयक समंको का प्रयोग किया गया है। अतः यदि उनमें कोई दोष रहे होंगे तो उनका प्रभाव निश्चित रूप से प्रस्तुत शोध पर पड़ेगा।
2. आर्थिक नीति में परिवर्तन क्यों किए गए, उनकी राजनैतिक पृष्ठभूमि क्या थी, इसका विश्लेषण प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में नहीं किया गया है।
3. विषय से सम्बन्धित वर्ष वर्ष 1991–92 से 1997–98 तक तथा वर्ष 1998–99 से 2004–05 तक के समंको को शोध प्रबंध में सम्मिलित किया गया है।
4. बैंकों का कार्य निष्पादन मापने के अनेक उपाय हैं, लेकिन शोध प्रबंध में केवल लाभक्षमता के आधार पर कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है।

➢ उपसंहार :–

यह शोध प्रबंध इस विचार से अभिप्रेरित रहा है कि जिस प्रकार रक्त की एक बूंद के द्वारा संपूर्ण रक्त का विश्लेषण किया जा सकता है, उसी प्रकार एक बैंक के अध्ययन के द्वारा सम्पूर्ण बैकिंग उद्योग पर आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव का अध्ययन हो सकता है। यह शोध प्रबंध न केवल आर्थिक उदारीकरण के बैकिंग तंत्र पर प्रभाव को समझने में सहायता देगा, अपितु यह बैंकों को भी अपना कार्य निष्पादन उन्नत बनाने में सहायता प्रदान करेगा। इस शोध प्रबंध से न केवल बैंकों को अपितु नीति निर्धारकों को भी चिंतन और विश्लेषण के लिए आवश्यक आधार प्राप्त होगा। आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव का अध्ययन प्रत्येक बैंक शाखा या प्रत्येक बैंक कर्मचारी स्तर पर से लेकर संपूर्ण बैंकिंग तंत्र पर हो सकता है। अतः भविष्य में भी इस दिशा में शोध की पर्याप्त संभावनाएँ विद्यमान हैं।

परिशिष्ट

संदर्भ ग्रंथ सूची /प्रतिवेदन/सांख्यिकी सामग्री/अधिकारिक प्रकाशन

1. Basu, S.K. - Recent banking development, The Book Exchange, Calcutta, 1982
2. Nigam, B.M.L. - Banking and Economic growth, Vora and company, Mumbai
3. "Economic Survery" - भारत सरकार द्वारा विभिन्न वर्षों के लिए प्रकाशित।
4. "Financial Analysis of Banks" - इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, मुम्बई।
5. "Monthly Reviews" - पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रकाशित।
6. "PNB Bulletin" - पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रकाशित।
7. "Annual Reports" तथा Report on Trend and Progress of Banking in India - रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित।

8. "Report of the Committee on the functioning of Public Sector Banks", (1976) - रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक द्वारा प्रकाशित।
9. "IBA Bulletin" विभिन्न मासिक एवं वार्षिक अंक, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, मुम्बई द्वारा प्रकाशित ।

डॉ. मनीष कुमार जैन
सहायक प्राध्यापक , रुकमादेवी पन्नालाल लड्ढ़ा माहेश्वरी महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)